



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2006/चैत्र 6, 1928

No. 49]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2006/CHAITRA 6, 1928

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2006

सं. 16-31/2004-एफए.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के पैरा (i) के साथ पठित धारा 36 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य प्रलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत जारी आदेश/अधिसूचना के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:—

(i) यह विनियम "लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (चौथा संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 4)" कहा जाएगा।

(ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2004 के खण्ड I के अंतर्गत विनियम 1 में खण्ड (2) तथा उसमें उल्लिखित विषयवस्तु के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(2) यह विनियम ऐसे प्रत्येक सेवा प्रदाता पर लागू होगा, जो निम्नलिखित दूरसंचार कार्यकलापों में से किसी एक या अधिक से सम्बद्ध हो:

- (i) बेसिक टेलीफोन सेवा
- (ii) राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा
- (iii) अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा
- (iv) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा
- (v) वेरी स्माल अपचर टर्मिनल सेवा (वीसैट)
- (vi) रेडियो पेजिंग सेवा
- (vii) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा
- (viii) ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सेवा और
- (ix) इंटरनेट सेवा

और जिसका पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों तथा कार्यकलापों की बिक्री तथा सप्लाय से कुल पच्चीस करोड़ रुपए या ज्यादा का टर्नओवर रहा हो।"

3. लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2004 के खण्ड II के अन्तर्गत विनियम 4 में खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(2) (क) ऐसे सेवा प्रदाता जिन पर यह विनियम लागू होता है, वे प्रतिवर्ष पुराने लागत लेखों के आधार पर विनियम 4 (1) में उल्लिखित रिपोर्टें तैयार करेंगे।

(ख) ऐसे सेवा प्रदाता को जिनपर यह विनियम लागू होता है, और जो निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उन्हें प्रत्येक दूसरे वर्ष परिवर्तित लागत लेखों के आधार पर रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी,

- (i) बेसिक टेलीफोन सेवा;
- (ii) राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा;
- (iii) अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा; और
- (iv) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

परन्तु यदि, ऊपर उल्लिखित सेवाओं में से एक विशेष सेवा उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाता को लाइसेंस जारी करने के बाद से तीन वर्ष से कम की अवधि हो तो उस सेवा के लिए परिवर्तित लागत लेखों पर आधारित वित्तीय रिपोर्ट तैयार न की जाए।”

4. लेखा पृथक्करण विनियम, 2004 पर रिपोर्टिंग प्रणाली के खण्ड II के अंतर्गत विनियम 5 में खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(2) उन सेवा प्रदाताओं को जो विनियम 4 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित लागत लेखों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं उन्हें प्रत्येक दूसरे वर्ष प्राधिकरण को वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर परिवर्तित लागत लेखों पर आधारित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।”

5. विनियम में शामिल मामलों को स्पष्ट करने के लिए एक विनियम के साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न किया गया है।

इन्दु लिबरहान, प्रधान सलाहकार (एफए एवं आईएफए)

[विज्ञापन III/IV/142/2005/असा.]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. लेखा पृथक्करण विनियम, 2004 पर रिपोर्टिंग प्रणाली ऐसे सभी सेवा प्रदाताओं पर लागू होगी जो मौजूदा विनियम (1) में विनिर्दिष्ट 9 दूरसंचार सेवाओं में से किसी भी सेवा को मुहैया करा रहे हैं। इन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक वर्ष पुराने लागत लेखांकन के आधार पर लेखा पृथक्करण रिपोर्टों को और प्रत्येक दूसरे वर्ष परिवर्तित लागत लेखांकन के आधार पर तैयार करना अपेक्षित है।

विनियम का लागू होना

2. इस वर्ष अधिकांश सेवा प्रदाता मुख्यतः छोटे सब्सक्राइबर आधार वाले आईएसपीएस, पीएमआरटीएस ऑपरेटरों, रेडियो पेजिंग ऑपरेटर, प्राधिकरण को लेखा पृथक्करण रिपोर्ट जमा कराने में असफल रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा उन सभी सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिन्होंने लेखा पृथक्करण रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं किया और इस प्रकार विनियम के आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है। सेवा प्रदाताओं जैसे पीएमआरटीएस ने कारण बताओ नोटिस के अपने लिखित उत्तर में उल्लेख किया है कि पीएमआरटीएस ऑपरेटरों का टर्नओवर कम है इसलिए लेखा पृथक्करण विनियम, पीएमआरटीएस उद्योगों पर एक बोझ है। इसके अलावा, अधिकांश पीएमआरटीएस ऑपरेटर, स्टैंडअलोन ऑपरेटर हैं जो एकल उत्पाद मुहैया कराते हैं और इसप्रकार इनके लेखों का लेखा पृथक्करण करना कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं करता है। दूसरी ओर अधिकांश रेडियो पेजिंग ऑपरेटरों ने अपने लाइसेंस को सरेण्डर कर दिए हैं। अधिकांश छोटे आईएसपी ने भी लेखा पृथक्करण रिपोर्ट तैयार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। प्राधिकरण द्वारा कारण बताओ नोटिस के विभिन्न प्रत्युत्तरों की काफी ध्यानपूर्वक जांच की गई और प्राधिकरण का मत है कि छोटे टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं पर लेखा पृथक्करण एक अनुचित बोझ है और इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि लेखा पृथक्करण केवल उन कंपनियों पर लागू किया जाएगा जिनकी पिछले वित्त वर्ष में कम से कम 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो।

3. प्राधिकरण ने यह समझा कि लेखा पृथक्करण विनियम का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रक्रियाओं जैसे कि क्रॉस सब्सिडी, प्रेडेटरी मूल्य निर्धारण आदि की जांच करना तथा उसे रोकना है। दूरसंचार कंपनियां जिनका टर्नओवर कम है, सामान्यतः इस प्रकार गैर प्रतिस्पर्धात्मक आचरण में संलिप्त होने की स्थिति में नहीं होती हैं, अतः सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जिनका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए अथवा इससे कम है, को लेखा पृथक्करण रिपोर्ट को तैयार करने और दायर करने से छूट देना उपयुक्त समझा गया।
4. लेखा पृथक्करण रिपोर्ट का अन्य मुख्य उद्देश्य टैरिफ निर्धारण के लिए लेखा-परीक्षित लागत आंकड़े मुहैया कराना था। चूंकि 25 करोड़ अथवा इससे कम के टर्नओवर वाले अधिकांश सेवा प्रदाताओं द्वारा पीएमआरटीएस, इंटरनेट, रेडियो पेजिंग आदि जैसी सेवा मुहैया कराई जा रही है और जिसकी टैरिफ में प्रविरिति है, इसलिए उनका लेखा पृथक्करण रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा, कम टर्नओवर अपने आप में सामान्यतः नेटवर्क का कम इस्तेमाल अथवा परिचालन कम होने का द्योतक है। इस प्रकार की कंपनियों के लागत आंकड़े टैरिफ निर्धारण के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकते हैं।
5. लेखा पृथक्करण विनियम लागू करने के लिए छूट की सीमा निर्धारित करते हुए प्राधिकरण ने विभिन्न विकल्पों पर विचार किया। प्राधिकरण ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लागत लेखा टेलीकॉम नियमों में भी, पिछले वर्ष में न्यूनतम 10 करोड़ या उससे कम टर्नओवर वाली उन कंपनियों के लिए नियमों को लागू करने के संबंध में इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की उच्च सीलिंग निर्धारित करने से वीसैट जैसी सेवाओं में कम मार्केट शेयर वाले एकल ऑपरेटरों को छूट मिलेगी। लगभग 10 करोड़ रुपए की कम सीलिंग के परिणामस्वरूप पीएमआरटीएस जैसी सेवा उपलब्ध कराने वाले ऑपरेटरों अथवा अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में पर्याप्त मार्केट हिस्सेदारी वाले एकल ऑपरेटरों पर भी विनियम की प्रयोज्यता होगी। अतः प्राधिकरण के विचार में सेवा प्रदाता के लिए लेखा पृथक्करण विनियम के प्रयोजन से 25 करोड़ रुपए के टर्नओवर की सीलिंग की छूट उचित है।

93442/06-2

6. लेखा पृथक्करण विनियम की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने सभी एकल सेवा प्रदाताओं को छूट देने के विकल्प पर भी विचार किया। प्राधिकरण ने नोट किया कि बहुत से एकल ऑपरेटर प्रभावी हैं और उन्होंने अपने परिचालन क्षेत्र/मार्किट में काफी हिस्सेदारी पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे ऑपरेटर अपने मार्किट नेतृत्व और प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की स्थिति में हैं। अतः प्राधिकरण ने सभी एकल टेलीकॉम ऑपरेटरों को लेखा पृथक्करण के मामले में छूट न देने का विनिश्चय किया है।

परिवर्तित लागत लेखांकन के आधार पर लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट फाइल करने से छूट।

7. लेखांकन पृथक्करण विनियम के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्ष परिवर्तित लागत लेखा पृथक्करण रिपोर्ट तैयार की जानी होती है और उसे प्राधिकरण के समक्ष दायर करना होता है। विनियम के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2004-05 दूसरा वर्ष था। अतः बहुत से सेवा प्रदाताओं के लिए प्राधिकरण के समक्ष परिवर्तित लागत लेखा पृथक्करण रिपोर्ट फाइल करना आवश्यक था। बहुत से सेवा प्रदाता विशेषकर आईएसपीएस, पीएमआरटीएस ऑपरेटरों ने परिवर्तित लागत के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने में अक्षमता जाहिर की और कहा कि ऐसी रिपोर्टें तैयार करना छोटे ऑपरेटरों पर भार है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर संघ ने भी परिवर्तित लागत लेखा पृथक्करण रिपोर्ट तैयार करने से आईएसपी को छूट देने का अनुरोध किया।

8. टेलीकॉम सेक्टर में प्रौद्योगिकीय बदलाव और लागत घटना सामान्य बात है। कभी-कभी पुराने आंकड़ों पर आधारित सेवाओं की लागत से ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं जो कि वर्तमान लागत के आधार से भिन्न होते हैं। विभिन्न टेलीकॉम रेगुलेटरों द्वारा परिवर्तित/वर्तमान लागतों पर आधारित इंटरकनेक्शन यूसेज, पोर्ट आदि की लागत सामान्य है। प्राधिकरण ने टेलीकॉम सेवाओं की लागत में परिवर्तित लागत के महत्व को भी ध्यान में रखते हुए लेखा पृथक्करण विनियम बनाया है। बहरहाल, इन वर्षों में बहुत से क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में परिपक्वता आई है और प्राधिकरण ने बहुत सी सेवाओं के लिए टैरिफ का

विनियम बंद कर दिया है। वर्तमान में प्राधिकरण सिर्फ आइयूसी और आईपीएलसी तथा डीएलसी जैसे कुछ टैरिफों का ही विनियम कर रहा है। अतः प्राधिकरण का विचार है कि निकट भविष्य में बहुत सी सेवाओं के लिए परिवर्तित लागत लेखों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः प्राधिकरण ने यह विनिश्चय किया कि एक्सेस प्रदाता, एनएलडीओ और आईएलडीओ के अलावा अन्यो को परिवर्तित लागत लेखों को तैयार करने से छूट होगी। बहरहाल, यदि आवश्यकता पड़ी तो प्राधिकरण अन्य सेवा प्रदाताओं पर परिवर्तित लागत लेखांकन की प्रयोज्यता की समीक्षा कर सकता है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2006

No. 16-31/2004-FA.— In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with para (i) of clause (b), sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India, Service Providers (Maintenance of Books of Accounts and Other Documents) Rules, 2002 and the order/notification issued thereunder, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Regulation namely:

1. Short title, extent and commencement: -

- (i). This Regulation shall be called "The Reporting System on Accounting Separation (Forth Amendment) Regulation, 2006 (4 of 2006)".
- (ii) The Regulation shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In regulation 1 under Section I of the Reporting System on Accounting Separation Regulation, 2004, for clause (2) and contents thereof, the following shall be substituted, namely:

"(2) This Regulation shall apply to every service provider, which is engaged in any one or more of the following telecommunication activities, namely: -

- (i) Basic Telephone Service;
- (ii) National Long Distance Service;
- (iii) International Long Distance Service;
- (iv) Cellular Mobile Telephone Service;
- (v) Very Small Aperture Terminal Service (VSAT);
- (vi) Radio Paging Service;
- (vii) Public Mobile Radio Trunk Service;
- (viii) Global Mobile Personal Communication Service; and
- (ix) Internet Service_

and having an aggregate turnover of Rupees twenty five crore or more, made from the sale or supply of all its products or activities during the preceding financial year.”

3. In regulation 4 under Section II of the Reporting System on Accounting Separation Regulation, 2004, for clause (2) the following shall be substituted, namely:

“(2) (a) The service providers to whom this Regulation applies shall every year prepare Reports mentioned in Regulation 4 (1) on the basis of historical cost accounting.

(b) The service providers to whom this Regulation applies shall also prepare reports every second year on the basis of replacement cost accounting if they are providing any one or more of the following services, namely:-

- (i) Basic Telephone Service;*
- (ii) National Long Distance Service;*
- (iii) International Long Distance Service; and*
- (iv) Cellular Mobile Telephone Service.*

Provided that if less than three years have elapsed since issue of the license to a service provider to provide a particular service from amongst the services mentioned above, the financial reports based on replacement cost accounting may not be prepared for that service.”

4. In regulation 5 under Section II of the Reporting System on Accounting Separation Regulation, 2004, for clause (2), the following shall be substituted, namely:

“(2) The service providers who are required to prepare reports on the basis of replacement cost accounting in accordance with the provisions of sub-clause (b) of clause (2) of regulation 4 shall also submit reports based on the replacement cost accounting every second year within six months of the end of the accounting year to the Authority.”

5. This Regulation contains an explanatory memorandum to provide clarity to matters covered under the Regulation.

Explanatory Memorandum

1. The Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2004 is applicable to all service providers providing any of the nine specified telecom services in the existing regulation (1). Every year these service providers are required to prepare accounting separation reports on the basis historical cost accounting and every second year on the basis of replacement cost accounting.

Applicability of the Regulation

2. This year many service providers, mainly ISPs with a small subscriber base, PMRTS operators, Radio Paging Operators failed to file accounting separation reports with the Authority. The Authority had issued show cause notices to all service providers who failed to submit accounting separation reports in time and therefore comply with the requirements of the regulation. The service providers like PMRTS have written in their replies to the show cause notice that PMRTS operators have small turnovers and therefore Accounting Separation Regulation is a burden on the PMRTS industry. Moreover most PMRTS operators are standalone operators providing single products and therefore accounting separation of their accounts may not serve any useful purpose. On the other hand most Radio Paging Operators have surrendered license. Many small ISPs have also written about their inability to prepare accounting separation reports. The Authority has very carefully examined various responses to the show cause notices and is of the view that accounting separation may be causing undue burden on service providers having small turnovers and decided that the accounting separation shall be applicable to only those companies which had a turnover of a minimum of Rs 25 crores for the preceding financial year.

3. The Authority also recalled that the main objectives of the Accounting Separation Regulation was to examine and check anti-competitive practices like cross subsidy, predatory pricing etc. Telecom companies having low turnovers are generally not in a position to practice such anti competitive behaviour and therefore found it fit to exempt all telecom service providers having turnover of Rs 25 crores or below from preparing and filing accounting separation reports.

4. The other main objective of the Accounting separation reports was to provide audited cost figures for tariff setting. Since, most service providers with turnover of Rs 25 crores or below are providing service like PMRTS, Internet, Radio paging etc and for which tariffs are forborne, their accounting separation reports may not be required. Moreover low turnover generally represents under utilization of network or smaller

nature of the operation itself. The cost figures for such companies may not be very useful for tariff setting

5. While deciding limits for exemption on applicability of the accounting separation regulation, Authority considered various options. The Authority also took note that the Cost Accounting Telecom Rules notified by the Ministry of Finance has a similar provisions on applicability of the Rules for only those companies having a minimum turnover of Rs 10 crores or less for the previous year. Fixation of a higher ceiling of around Rs 100 crores would have exempted many standalone operators having significant market shares in services like VSAT. A lower ceiling of around Rs 10 crores may have resulted in applicability of the regulation on operators providing standalone service like PMRTS or on standalone operators having insignificant market share when compared to its competitors. The Authority therefore found that a ceiling of Rs 25 crores turnover is appropriate for exempting service providers from the applicability of the Accounting Separation Regulation.

6. The Authority while considering applicability of the Accounting Separation Regulation also considered other option of exempting all standalone service providers, providing single service. The Authority noted that many standalone operators are dominant and have captured major market share in areas or markets in which they are operating. Such operators are in a position to take advantage of their market leadership and scuttle competition. The Authority has therefore decided against exempting all standalone telecom operators from accounting separation.

Exemption from filing Accounting Separation reports on the basis of Replacement Cost Accounting.

7. As per the Accounting Separation Regulation, every second year, the replacement cost accounting separation reports are to be prepared and filed with the Authority. The financial year, 2004-05 was the second year of implementation of the Regulation and therefore many service providers were required to file the replacement cost accounting separation reports with the Authority. Many service providers especially ISPs, PMRTS operators expressed inabilities to prepare reports on the basis of the replacement costs and stated that preparation of such reports are burden on small operators. The Internet Service Provider Association also requested to exempt ISPs from preparation of the replacement cost accounting separation reports.

8. In the telecom sector technological changes and declining costs are common. The costing of services based on historical accounts at times give very different results from those based on the current costs. The costing of interconnection usage, Ports etc based on replacement/current costs by various telecom regulators is common. The Authority also had framed Accounting Separation Regulation keeping in mind the importance of the replacement cost in costing of telecom services. However, over these years competition in many areas have matured and the Authority has stopped regulating tariffs for most of the services. The Authority is presently regulating only IUC and few tariffs like IPLC and DLC. The Authority, therefore, considers that replacement cost accounts for many services may not be needed in the near future and therefore decided that except Access Providers, NLDOs and ILDOs, others may be exempted from the requirement of preparing replacement cost reports. However shall the need arise, the Authority may review the applicability of replacement cost accounting on other service providers.